

ऐसे सलाहकारों से भगवान बचाए

प्रवीण चक्रवर्ती तमिलनाडु से राज्यसभा की सीट चाहते थे, मु.मंत्री स्टालिन ने देने से मना कर दिया तो प्रवीण कांग्रेस के सबसे पुराने और सफल गठबंधन को तोड़ने में जुट गए

कुख्यात गैंगस्टर ने खनन कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी

जयपुर, 2 जनवरी। अशोक नगर थाना इलाके में कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा की गैंग के गुर्गों ने एक खनन कारोबारी को वाट्सऐप पर कॉल कर 5 करोड़ करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। जिसके बाद पीडित ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने वाट्सऐप पर आए नंबरों के आधार पर जांच शुरु कर दी है।

एएसआई राजकुमार ने बताया कि पीडित सी- स्क्रीम निवासी खनन कारोबारी हैं और उसके मोबाइल पर 30 दिसम्बर को इंटरनेशनल मोबाइल नंबरों से कई बार कॉल आई। बार –बार फोन

■ पुलिस ने वाट्सऐप पर आए नंबरों के आधार पर जाँच शुरु की

आने पर पीडित ने कॉल रिसीव की तो अंजान युवक ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और राहुल रिणाऊ का बदमाश बताया और गाली-गलौच करते हुए 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। जिसके बाद बदमाश ने 31 दिसम्बर को फिर से अलग मोबाइल नंबर से कॉल किया और वॉयस नोट भी भेजे। पांच करोड़ नहीं देने पर बदमाश ने परिवार सदस्यों को भी जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीडित की शिकायत पर अनजान इंटरनेशनल नंबरों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

-रेणु मिश्रल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 2 जनवरी। राहुल गांधी की कोर एडवाइजरी काउंसिल “जय जगत” के सदस्य कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत और दीर्घकालिक गठबंधन, जो द्रमुक (डीएमके) के साथ तमिलनाडु में है, को अस्थिर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसके साथ ही, जय जगत ग्रुप में राहुल गांधी के वफादारों के बीच गंभीर मतभेद भी उभरकर सामने आए हैं।

यह कहानी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर आधारित है, न कि किसी वैचारिक ढांचे पर, यह बात कही एक वरिष्ठ नेता ने, जो राहुल गांधी के चारों ओर फैली इस अव्यवस्था से वाकिफ है।

प्रवीण चक्रवर्ती और गिरीश चोडनकर, जो तमिलनाडु के कांग्रेस प्रभारी हैं, चाहते हैं कि कांग्रेस द्रमुक के साथ अपना गठबंधन तोड़कर अभिनेता विजय की पार्टी के साथ गठबंधन करें।

- जैसा कि विदित ही है, प्रवीण चक्रवर्ती व गिरीश चोडनकर कांग्रेस की ओर से प्रभारी हैं, तमिलनाडु के।
- स्टालिन की प्रवीण चक्रवर्ती से नाराज़गी का कारण है, प्रवीण, स्टालिन की दृष्टि में विश्वासयोग्य व्यक्ति नहीं हैं। प्रवीण ने अपने एक नज़दीकी मित्र, जो डीएमके सरकार में मंत्री भी थे, के साथ हुई एक निजी बातचीत को टेप करके उजागर कर दिया था।
- मित्र, उस टेप में डीएमके के नेतृत्व को खुलकर भला-बुरा कह रहे थे। अतः, टेप सार्वजनिक होने पर मंत्री को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। स्टालिन इस धोखे व कृतघ्नता को भूलने को तैयार नहीं हैं और वे प्रवीण के साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं रखना चाहते।
- इसी प्रकार, कांग्रेस की वर्तमान सोच है कि अगर गठबंधन पुनः सत्ता में आता है तो कांग्रेस को सरकार में भागीदार बनना चाहिए। पर, चिदंबरम की राजनीति को यह सोच माफिक नहीं आ रहा, अतः वे कांग्रेस के सत्ता में भागीदार बनने की सख्त खिलाफत कर रहे हैं।
- तमिलनाडु में कांग्रेस की स्थिति काफी गफलत में है, सलाहकारों की अजीबोगरीब और कई बार परस्पर विरोधी सलाहों के कारण। अतः अभी कहना मुश्किल है कि कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी, तमिलनाडु में और उसका क्या परिणाम निकलेगा।

दरअसल, प्रवीण चक्रवर्ती तमिलनाडु से द्रमुक के जरिए राज्यसभा की सीट चाहते हैं, लेकिन स्टालिन इस

पर बिल्कुल भी विचार करने को तैयार नहीं हैं। इसीलिए प्रवीण चक्रवर्ती यह कोशिश कर रहे हैं।

पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तीन उच्च न्यायालयों में नए चीफ जस्टिस नियुक्त, तीन अभी भी लंबित

सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम द्वारा गत माह की गई सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार ने नियुक्तियाँ की हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 2 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम द्वारा पिछले महीने की गई सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए, केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को दो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को दो अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। एक मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण की भी अधिसूचना जारी की गई है।

जस्टिस सोमेन सेन, जो वर्तमान में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, को केरल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है। यह स्थानांतरण 9 जनवरी 2026, को, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के रिटायरमेंट के बाद, प्रभावी होगा।

जस्टिस रेवती पी मोहिते डेरे, जो (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- कोलीजियम ने गत माह 18 दिसंबर को 6 उच्च न्यायालयों के लिए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें भेजी थीं।
- केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सोमेन सेन को केरल हाई कोर्ट का और बॉम्बे हाई कोर्ट की जज, जस्टिस रेवती पी मोहिते डेरे को मेघालय हाई कोर्ट का और उड़ीसा हाई कोर्ट के जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई जिन तीन सिफारिशों को लंबित रखा गया है, वे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, जिन्हें उत्तराखंड हाई कोर्ट का, जस्टिस एम एस सोनक (बॉम्बे हाई कोर्ट), जिन्हें झारखंड हाई कोर्ट का और केरल हाई कोर्ट के जस्टिस ए एम मुश्ताक, जिन्हें सिक्किम हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की अनुशंसा की गई थी।

एक सप्ताह में 25 लाख श्रद्धालु आए मथुरा वृंदावन

मथुरा, 02 जनवरी। कान्हा की नगरी में 25 दिसंबर से अब तक में लगभग 25 लाख श्रद्धालुओं ने ब्रज के विभिन्न मंदिरों में माथा टेका है। भक्ति का यह सैलाब पिछले वर्षों के सभी रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है।

जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष इसी अवधि के

- जिला प्रशासन ने बताया है कि यह एक रिकॉर्ड है और इसका कारण है सुगम यातायात और बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर।

दौरान यह आंकड़ा करीब 15 से 18 लाख के आसपास था। सुगम यातायात और बेहतर बुनियादी ढांचे के कारण इस साल 30-40 प्रतिशत अधिक श्रद्धालु मथुरा-वृंदावन पहुंचे हैं। विशेषकर श्री बांके बिहारी मंदिर और गोवर्धन परिक्रमा में इस बार "पैर रखने की भी जगह" नहीं दिख रही है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

“ गिग ’’ कर्मचारियों को सोशल सिक्युरिटी का लाभ कैसे मिले?

सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून में कई शर्तें लगाई हैं, गिग वर्कर्स पर, इस लाभ का हकदार बनने के लिए

- पहली महत्वपूर्ण शर्त है कि “गिग वर्कर्स” को किसी भी एक कंपनी/प्लेटफार्म के यहाँ कम से कम 90 दिन काम करना होगा, तभी उसे स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना के समय इंश्योरेंस आदि का हक मिल सकेगा।
- वर्कर्स का नब्बे दिन का कार्यकाल उसी दिन से मान लिया जाएगा, जब से पहले दिन से पैसे मिलेंगे। इसका कोई महत्व नहीं होगा कि उसे कितने कम या ज्यादा पैसे मिलते हैं।
- हर “गिग वर्कर” को अपने आधार कार्ड का उपयोग करते हुए, अपने आपको रजिस्टर करना होगा और काम देने वाली कंपनी/प्लेटफार्म को एक सेंट्रल पोर्टल पर वर्कर के बारे में जानकारी डालनी होगी, जिसमें वर्कर को यूनिक आईडी मिलेगी तथा वर्कर को एक आईडी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उसकी फोटो भी लगी होगी।
- एक सरकारी अधिकारी, प्लेटफार्म से प्रति वर्कर आर्थिक योगदान इकट्ठा करके, सोशल सिक्युरिटी फण्ड में डालेगा, जिससे वर्कर को सोशल सिक्युरिटी की सुविधा फायर्नैस की जाएगी।

ठेकेदार या फ्रीलांसर के रूप में काम करते हैं। इनमें कैब ड्राइवर, फ़ूड डिलीवरी बॉय, फ्रीलांस लेखक, डिजाइनर और कंसल्टेंट आदि शामिल हैं। ये नियमित वेतन के बजाय प्रोजैक्ट-दर-प्रोजैक्ट पैसा कमाते हैं और काम

दूँदने के लिए अक्सर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पूर्णकालिक नौकरी के बजाय, इसे टुकड़ों में किया जाने वाला काम (गिग) कहा जाता है

मसौदा नियमों के 10 मुख्य बिंदु

इस प्रकार हैं: स्वास्थ्य, जीवन और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं के लिए गिग वर्कर को कम से कम 90 दिनों तक एक ही एग्रीगेटर के लिए काम करना होगा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में शुक्रवार को 66 उड़ानें रद्द

नयी दिल्ली, 02 जनवरी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को 66 उड़ानें रद्द रही।

दिल्ली में आज कोहरा कम था, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में कोहरे के कारण वहां से आने वाली और वहां जाने

- हालांकि दिल्ली में आज कोहरा कम था पर अन्य शहरों में कोहरा होने की वजह से फ्लाइट्स कैंसल की गईं।

वाली उड़ानें रद्द रही। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न विमान सेवा कंपनियों ने आज दिल्ली आने वाली 32 और यहां से जाने वाली 34 उड़ानें रद्द कीं। इसके अलावा कई उड़ानों में देरी की भी सूचना है।

उल्लेखनीय है कि आज दिल्ली में रनवे पर दृश्यता ठीक रही, लेकिन दूसरे शहरों में कोहरा रहा।

मुसलमान अक्सर हिंदुओं को धमकाते रहे हैं, और हमले करते रहे हैं, यह मुख्य रूप से ममता बनर्जी सरकार था।

वरिष्ठ भाजपा नेता इस बात से पूरी तरह आश्चस्त हैं कि सीमा पार हो रही इन घटनाओं का भारतीय जनता को मुस्लिम मुद्दे के प्रति सोच पर गहरा असर पड़ेगा। इसका असर वोटिंग पैटर्न पर भी पड़ेगा।

ममता बनर्जी जानती हैं कि उनके चारों ओर क्या हो रहा है। वे राज्य में भाजपा के हर निशान को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- दूसरी ओर भाजपा नेता अमित शाह बंगाल में डटे हुए हैं, घटनाक्रम का पूरा राजनीतिक लाभ लेने के लिए।
- तनावग्रस्त ममता बनर्जी ने अजीबोगरीब आदेश व प्रतिक्रिया देनी शुरू की।
- पहले तो अपने कैंडर को आदेश दिए कि अमित शाह के स्वागत में लगे सभी बैनर-पोस्टर, होर्डिंग को हटवाओ, जिससे ऐसा लगे कि उनकी उपस्थिति का कोई असर नहीं है।
- फिर ममता जी ने वक्तव्य दिया कि वे उदार दिल हैं, अतः उन्होंने अमित शाह को शहर में घूमने-फिरने, राजनीतिक प्रचार की अनुमति दे रखी है, अन्यथा वे अमित शाह को उनके होटल तक सीमित कर सकती थीं, तथा उनके बाहर निकलते ही, बंगाल की पुलिस उनको घेर लेती और उनके सारे प्रोग्राम थम जाते।
- पर, अहम सवाल यह है कि क्या राज्य की पुलिस देश के गृह मंत्री को, देश के किसी भी राज्य में घूमने-फिरने से रोक सकती है और क्या राज्य की पुलिस ऐसे आदेश का अनुपालन करने से इनकार नहीं करेगी, आखिर राज्यों की पुलिस भी देश के गृह मंत्रालय की रज़ामंदी से व इज़ाज़त से ही तो राज्य में काम करती है, तैनात होती है।